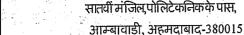
# केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)

## O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,

कर भवन,

GST Building, 7th Floor,, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-

380015



: 079-26305065

टेलेफेक्स : 079 - 26305136

फाइल संख्या : File No : V2(74)101 /AHD-III/2016-17/10367 ₺ 10372 क

अपील आदेश संख्या :Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-0147-17-18 ख दिनाँक Date :13.11.2017 जारी करने की तारीख Date of Issue: ० १२०१२ श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals)Ahmedabad

अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-॥ आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश : AHM-CEX-003-DC-050-2016 दिनाँक : 30.12.2016से सृजित

Arising out of Order-in-Original: AHM-CEX-003-DC-050-2016, Date: 30.12.2016 Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Div:Kalol, Ahmedabad-III.

अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता ध

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Morakhia Metal & Alloy Pvt. Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथारिथिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

# भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन ः Revision application to Government of India:

- केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।
- A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :
- यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।
- In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क र्यातित स्वाकर (अभीतः भागाना में Side रहा में कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में नियातित

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside (b) India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to country or territory outside India. ENT. TO THE

- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (C) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केंडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।
- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए—8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल—आदेश एवं अपील आदेश की दो—दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35—इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर—6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपीलः— Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35— णबी/35—इ के अंतर्गत:—

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलों के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ—20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद—380016.

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए–3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सिहत जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/— फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रिजस्टार के नाम से रेखाकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any

nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि--1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर क्त.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall beer a court fee stamp of Rs.6.50 paisa as prescribed under scheduled-l item of the court fee Act, 1975 as amended.

- इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में
- Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९४४ की धारा ३५फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-२) अधिनियम २०१४(२०१४ की संख्या २५) दिनांक: ०६.०८.२०१४ जो की वितीय अधिनियम, १९९४ की धारा ८३ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
- सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- amount determined under Section 11 D;
- amount of erroneous Cenvat Credit taken; (ii)
- amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

ightarrowProvided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal of Ration (3/4) payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute. penalty, where penalty alone is in dispute."

### ORDER-IN-APPEAL

This appeal has been filed by M/s Morakhia Metal & Alloys Pvt Ltd, GIDC-IV, Chhatral, Taluka Kalol, District-Gandhinagar ["the appellant"] against Order-in-Original No.AHM-CEX-003-DC-050-2016 dated 30.12.2016 [impugned order] passed by the Deputy Commissioner of Central Excise, Kalol Division.

- 2. Based on a Audit Objection, a show cause notice dated 21.01.2016 was issued to the appellant, alleging that:
- the raw materials, valued at Rs.24,30,432/- sent for job work were not received back within 180 days as per provisions of Rule 4 (5)(a) of Cenvat Credit Rules, 2004 (CER) which attracts payment of central excise duty amounting to Rs.3,00,401/- with interest under Section 11 A and 11AA of Central Excise Act, 1944 (CEA) respectively and penalty equal to the duty amount under Section 11AC(1) of CEA.
- [ii] They had availed Cenvat credit of Rs.5,531/- on Refractory Materials falling under chapter 69 as an inputs instead of credit as Capital Goods which is not admissible and required to be recovered with interest and liable for penalty of Rs.5,531/- under Section 11 AC of CEA read with Rule 15 (2) of CER.
- [iii] they had availed excess Cenvat credit amounting to Rs.44,174/- on the bills raised by the Labour Contractor during 2012-13 which is required to be recovered with interest and liable for penalty of Rs.44,174/- under Section 11 AC of CEA read with Rule 15 (2) of CER.
- 3. The appellant has paid all the amount of Rs.3,00,401/-, Rs.5,531/- and Rs.44,174/- during the course of audit.
- 4. The adjudicating authority has confirmed all allegations and accordingly confirmed the demands with interest and imposed penalty equal to the amount of demand.
- 5. Being aggrieved, the appellant has filed the instant appeal on the grounds that:
- [i] the appellant has paid the amount Cenvat credit of Rs.3,00,401/- as per the provisions of Rule 4(5)(a) of CER and since the said rule does not stipulate other consequences i.e interest and penalty, the order passed by the adjudicating authority is required to be set aside. The appellant has relied on various case laws in their favour.
- [ii] The Cenvat credit for the goods in question is admissible under Capital goods, same cannot be disallowed merely because the credit was availed under input credit. They relied on case law of Modi Rubber Ltd-2000(119) ELT 197-Tri. LB
- [iii] They had taken the excess credit by mistake and reversed the same. Therefore, the same cannot be attributed to any of the ingredients of Rule 15(2) of CCR by reason of fraud, collusion etc.
- 6. Personal hearing in the matter was held on 01.11.2017. Shri P.G.Mehta Advocate appeared for the same on behalf of the appellant and reiterated the grounds of appeal. He further submitted additional submissions and copy of case

law in case of M/s Accurate Transformers Ltd reported at 2015 (315) ELT 271-Tri. Del.

- 7. I have carefully gone through the facts of the case and submissions made by the appellant. The limited issues to be decided in the instant case is relating to [i] demand of interest and penalty imposed in violation to provisions of provisions of Rule 4 (5)(a) of CER; [ii] availment of Cenvat credit as inputs instead of capital goods; and [iii] demand of interest and imposition of penalty on excess credit by mistake.
- As regards [i] above, I observe that the appellant had sen∉goods for job works outside to their factory premises which were not received within 180 days as stipulated under the provisions of provisions of Rule 4 (5)(a) of CER. I observe that the said provisions stipulates that "if the inputs or capital goods, as the case may be, are not received back iii) within the time specified under sub-clause (i) or (ii), as the case may be, by the manufacturer or the provider of output service, the manufacturer or the provider of output service shall pay an amount equivalent to the CENVAT credit attributable to the inputs or capital goods, as the case may be, by debiting the CENVAT credit or otherwise, but the manufacturer or the provider of output service may take the CENVAT credit again when the inputs or capital goods, as the case may be, are received back in the factory or in the premises of the provider of output service". In instant case, the appellant has debited the Cenvat credit attributable to the goods sent for job on pointed out by the Audit officer. Every delayed payment of interest is relevant. In the circumstances, interest is payable for such delay taken place in reversal of the credit. However, no penalty is imposable in view of case law cited by the appellant in case of M/s Accurate Transformers Ltd supra and Hon'ble Tribunal's decision in case of M/s Hi-Tech Blow Moulders Pvt Ltd [2016 (341) E.L.T. 419 (Tri. - Bang.)], wherein it has been held that "Inasmuch as we hold in favour of the assessee on the main issue, and the issue of reversal of credit on account of non-receipt of inputs sent to the job worker within a period of 180 days is a procedural lapse and inasmuch as the credit has been reversed along with interest even before the issue of show cause notice, we find no justifiable reason to impose penalty on the appellant and also on the Managing Director. The penalty is accordingly set aside. Both the appeals are decided in above manner". Accordingly, I set aside the penalty imposed.
- 9. As regards [ii] above, I observe that the appellant had availed Cenvat credit of Rs.5,531/- on Refractory Materials as input instead of credit as capital goods. If it is falls under capital goods, the appellant is eligible to take 50% of the amount as a credit of capital of goods as per provisions of CCR for the relevant year and remaining amount in the next year. Therefore, I considered the act on the part of the appellant as a mistake. Since the appellant is reverse the amount, only interest is payable. The penalty imposed is therefore set aside.

- 10. As regards [iii] above, I observe that the appellant has admitted the fact that they had taken excess credit of Rs.44,174/-and accordingly, they reversed the same. They requested for waiver of interest and penalty. Since they had taken the said amount excess, interest is payable. However, being a mistake on their part, I take a lenient from imposing penalty. Therefore, I set aside the same.
- 11. In view of above discussion, I partly allow the appeal filed by the appellant. The appeal stand disposed of accordingly.

(उमा शंकर)

आयुक्त (अपील्स )

Date: /11/2017.

**Attested** 

(Mohanan V.V)
Superintendent (Appeal)

# By RPAD

To M/s Morakhia Metal & Alloys Pvt Ltd, GIDC-IV, Chhatral, Taluka Kalol, District-Gandhinagar

# Copy to:-

- 1. The Chief Commissioner, CGST Zone, Ahmedabad.
- 2. The Commissioner, CGST, Gandhinagar
- 3. The Additional Commissioner, Gandhinagar.
- 4. The Addl./Joint Commissioner, (Systems), CGST, Gandhinagar
- 5. The Dy. / Asstt. Commissioner, CGST , Division, Kalol
- 6. Guard file.
- *7*/. P.A

